

तीन नरियात अवसंरचना योजनाओं को मंजूरी

संदर्भ

उल्लेखनीय है कि न्यून अवसंरचना के कारण भारत के नरियातों की प्रतस्पर्द्धात्मक क्षमता में कमी आ रही है। अतः केंद्र ने पहली बार मार्च में लॉन्च की गई एक स्कीम के तहत इस समस्या को संज्ञान में लिया। इसके साथ ही सरकार ने तीन प्रस्तावों को मंजूरी भी दे दी है जिनमें से पहली मंजूरी इम्फाल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक एकीकृत कार्गो टर्मिनल (Integrated Cargo Terminal-ICT) के निर्माण को दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- नरियात योजना के लिये व्यापार अवसंरचना (Trade Infrastructure for Export Scheme -TIES) की पहली बैठक 9 जून को सम्पन्न हुई थी। इस बैठक में चकित्सकीय उपकरणों की जाँच करने के लिये भारत में 'पहली समर्पित सुविधा' (first dedicated facility) की स्थापना के लिये आवेदन दिया गया था। इसे विशाखापत्तनम में स्थिति आंध्र प्रदेश के चकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है। जिसमें चार अलग-अलग सुविधाएँ होंगी और इनकी कुल लागत लगभग 169 करोड़ रुपए है।
- वर्ष 2015 में भारतीय चकित्सकीय उपकरण बाज़ार लगभग 4 बिलियन डॉलर का था और भारत से नरियात होने वाली इन वस्तुओं की कुल लागत वर्ष 2016 में तकरीबन 1 बिलियन डॉलर थी।
- हालाँकि अधिकार प्राप्त समिति ने कर्नाटक में 'तटीय काजू अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन' (Coastal Cashew Research and Development Foundation) की स्थापना के प्रस्ताव के लिये भी सैद्धांतिक रूप में मंजूरी दे दी है जिसकी कुल अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपए है।
- इम्फाल में एकीकृत कार्गो टर्मिनल के निर्माण की लागत 16.2 करोड़ रुपए है जिसमें नरियात योजना के लिये व्यापार अवसंरचना की हस्तिसेदारी 12.96 करोड़ तथा भारतीय विमान प्राधिकरण की हस्तिसेदारी 3.24 करोड़ रुपए की है।
- वदिति हो कि इम्फाल हवाई अड्डे पर कोई कार्गो सुविधा नहीं है और प्रस्तावित एकीकृत कार्गो टर्मिनल दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के लिये हवाई कार्गो आवागमन और वायु कनेक्टिविटी के एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

बाधाएँ क्या हैं ?

- वाणजिय वभिग संबंधी स्थायी समिति द्वारा मार्च 2016 में भारत में नरियात अवसंरचना पर तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, न्यून अवसंरचना और भारत में अवसंरचना के संचालन के तरीके वस्तुओं के वनिर्माण और नरियात में प्रतस्पर्द्धात्मकता को सुनिश्चित करने में दो प्रमुख बाधाएँ हैं।
- रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय नरियात अत्यधिक रसद लागतों (logistics costs) के कारण वैश्विक प्रतस्पर्द्धा से बाहर हो रहा है। भारत में रसद लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14% है जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं (जैसे-अमेरिका और यूरोपीय संघ) में यह सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 8% और 10% है।
- स्थायी समिति के अनुसार, उप इष्टतम रसद क्षमता के कारण रसद पर निर्भर कुछ निश्चित क्षेत्रों को उनकी बिक्री वापसी में 2% का नुकसान होगा। कुछ वर्ष पूर्व किये गए एसोचेम के एक अध्ययन में यह दर्शाया गया कि भारत को न्यून अवसंरचना के कारण अपने व्यापार में लगभग 11% का घाटा हुआ है।

क्या होगा प्रभाव ?

- यदि रसद लागतों को देश के सकल घरेलू उत्पाद के 14% से कम करके 9% कर दिया जाएगा तो भारत 50 बिलियन डॉलर रुपए तक की बचत कर सकता है। अतः वैश्विक बाजारों में घरेलू वस्तुएँ अधिक प्रतस्पर्द्धा हो जाएंगी। वाणजिय मंत्रालय के अनुसार, टीआईईएस का उद्देश्य नरियात अवसंरचना में अंतरालों को कम कर नरियात प्रतस्पर्द्धा को बढ़ावा देना है।